भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
09.08.2023 के
तारांकित प्रश्न सं. 297 का उत्तर

सवारी डिब्बा विनिर्माण उद्योग

***297. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:**
श्री कृष्ण पाल सिंह यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सवारी डिब्बा विनिर्माण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) देश में सवारी डिब्बा विनिर्माण सुविधाओं के विकास पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ग) रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के टियर 2 और टियर 3 शहरों में रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हाई-स्पीड पटरियों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) आईसीएफ सवारी डिब्बों के स्थान पर एलएचबी सवारी डिब्बों को लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

सवारी डिब्बा विनिर्माण उद्योग के संबंध में दिनांक 09.08.2023 को लोक सभा में डॉ. हिना विजयकुमार गावीत और श्री कृष्ण पाल सिंह यादव के तारांकित प्रश्न सं. 297 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): रेल मंत्रालय के अधीन इस समय तीन (03) सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाइयां हैं।

(ख): भारतीय रेल में सवारी डिब्बा विनिर्माण सुविधाएं विकसित करने के लिए लगभग 6,322 करोड़ रु. का कुल व्यय किया गया।

(ग): भारतीय रेल में स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण करना निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है और इन्हें आवश्यकतानुसार शुरू किया जाता है, जो परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन होती है। बहरहाल, स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्यों के स्वीकृत और निष्पादन के समय निचली श्रेणी के स्टेशनों की तुलना में उच्च श्रेणी के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

हाल ही में, भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार लाने जैसे स्टेशनों तक पहुंच में सुधार लाना, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लैंडस्केपिंग आदि करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन्हें विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करना शामिल है।

इस योजना में स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमॉडल एकीकरण, 'दिव्यांगजनों' के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथों का प्रावधान, आवश्यकतानुसार 'रूफ प्लाज़ा', लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर की चरणबद्ध योजना व व्यवहार्यता और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1309 रेलवे स्टेशन चिह्नित किए गए है, इनमें उत्तर प्रदेश में 156 स्टेशन, मध्य प्रदेश में 80 स्टेशन और महाराष्ट्र में 126 स्टेशन शामिल हैं।

(घ): वर्तमान में रेल मंत्रालय ने देश में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरीडोर परियोजना (एमएएचएसआर) स्वीकृत की है, जो जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। जून 2023 तक इस परियोजना पर 45,621 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित सात (7) हाई स्पीड रेल कॉरीडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है, इनमें से दो (2) कॉरीडोर उत्तर प्रदेश से और दो (2) कॉरीडोर महाराष्ट्र से गुजर रहे हैं:

(i) दिल्ली-वाराणसी
(ii) दिल्ली-अहमदाबाद
(iii) मुंबई-नागपुर
(iv) मुंबई-हैदराबाद
(v) चेन्नै-मैसूर
(vi) दिल्ली-अमृतसर
(vii) वाराणसी-हावड़ा

(ड.): भारतीय रेल ने 01.04.2018 से आईसीएफ डिज़ाइन के सवारी डिब्बों का उत्पादन बंद कर दिया है और मौजूदा आईसीएफ सवारी डिब्बों को यातायात की आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से एलएचबी सवारी डिब्बों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। भारतीय रेल ने 31.07.2023 तक 35,766 एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण किया है, जिनमें से पिछले 09 वर्षों के दौरान 33,299 एलएचबी सवारी डिब्बे विनिर्मित किए गए हैं।

******